नंदिग्राम टाईम्स

RNI NO. MAHHIN/2016/69743 EDITOR : SHAIKH JAHUR AHEMAD

Sunday 28th December 2025 | ● वर्ष - 9 | ● अंक 242 | ● पृष्ठ 04 | ● मूल्य - 2 रूपए | ● www.nandigramtimes.com

लद्दाख में पांच नए जिलों का परिचालन शुरू: उपराज्यपाल गुप्ता

जम्मू/लेह, 28 दिसंबर 2025 – लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने घोषणा की कि केन्द्रशासित प्रदेश में पांच नए जिलों — चांगथांग, जांस्कर, नुब्रा, शाम और द्रास — के सुचारु संचालन के लिए प्रशासनिक, बुनियादी ढांचे और मानव संसाधन की व्यवस्था पर कार्य तेजी से जारी है। इन जिलों के गठन की मंजूरी 25 अगस्त, 2025 को केंद्र सरकार द्वारा दी गई थी, जिससे लद्दाख में कुल जिलों की संख्या दो से बढ़कर सात हो जाएगी।

गुप्ता ने बताया कि इस परिवर्तन से शासन व्यवस्था जनता के और करीब आएगी, आवश्यक सेवाओं तक पहुंच सुधरेगी तथा लद्दाख की कठिन भौगोलिक स्थितियों में विकास-संबंधी असमानताओं को कम करने में सहायता मिलेगी। प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि जिले स्तर पर प्रशासनिक पहुंच बढ़ाने का लक्ष्य जनता के जीवन में वास्तविक सुधार लाना है। प्रतिनिधिमंडल ने भी पुष्टि की कि लंबे दूरी, कठोर जलवायु और सीमित प्रशासनिक पहुंच के कारण स्थानीय लोग परेशान रहते थे, और नए जिलों के गठन से सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी बेहतर होगी, आपदा प्रबंधन मजबूत होगा तथा स्थानीय समुदायों को सशक्त किया जाएगा। गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार लद्दाख के समग्र और समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध है और हितधारकों के साथ परामर्श की प्रक्रिया जारी रखी जाएगी।

NEWS DELHI | केंद्रीय गृहमंत्री का पश्चिम बंगाल वाला प्लान क्या है?

पहले पीएम मोदी अब अमित शाह, विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृहमंत्री का पश्चिम बंगाल वाला प्लान क्या है?

नई दिल्ली | पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कोलकाता यात्रा काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यह उनकी वर्ष की अंतिम प्रमुख राजनीतिक यात्राओं में से एक होगी, जिसमें पार्टी की संगठनात्मक तैयारियों, चुनावी रणनीति और विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) जैसे मुद्दों पर गहन चर्चा होगी। इससे पहले पीएम मोदी ने 19 दिसंबर को पश्चिम बंगाल की यात्रा की थी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, अमित शाह 29 दिसंबर की शाम को कोलकाता पहुंचेंगे और वहां 31 दिसंबर तक रहेंगे। यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया बंगाल दौरे के ठीक बाद हो रहा है, जो भाजपा की 2026 में ममता बनर्जी की टीएमसी (तृणमूल कांग्रेस) को चुनौती देने की मजबूत तैयारी को दर्शाता है।

शीर्ष स्थानीय नेताओं के साथ कोर ग्रुप की बैठक

यात्रा की शुरुआत सोमवार की रात को होगी, जब अमित शाह कोलकाता पहुंचते ही भाजपा के शीर्ष स्थानीय नेताओं के साथ कोर ग्रुप की बैठक करेंगे। यह बैठक पार्टी की आंतरिक तैयारियों और संगठनात्मक मजबूती पर केंद्रित रहेगी। इस दौरान राज्य इकाई के नेताओं से फीडबैक लिया जाएगा और आगामी चुनावों के लिए रोडमैप तैयार किया जाएगा।

30 दिसंबर को शाह का कार्यक्रम काफी व्यस्त रहेगा। सुबह से ही वे पार्टी के कोर ग्रुप और सामान्य नेताओं के साथ अलग-अलग बैठकों में शामिल होंगे। इस दिन वे मीडिया से मुखातिब होंगे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, जिसमें चुनावी मुद्दों, एसआईआर प्रक्रिया और टीएमसी सरकार की नीतियों पर हमला बोल सकते हैं।

इस्कॉन के प्रसिद्ध मंदिर में दर्शन

इसके अलावा, शाह इस्कॉन (इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस) के प्रसिद्ध मंदिर में दर्शन करेंगे। शाम को वे आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) के कोलकाता कार्यालय जाएंगे, जहां उनकी संघ के वरिष्ठ अधिकारियों और प्रचारकों के साथ लंबी बैठक होगी। इस बैठक में बंगाल के स्थानीय मुद्दों, संगठन विस्तार और चुनावी चुनौतियों पर विस्तृत मंत्रणा होगी।

यात्रा का समापन 31 दिसंबर को होगा, जब अमित शाह कोलकाता में एक वृहद कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में हजारों भाजपा कार्यकर्ता शामिल होंगे, जहां शाह उन्हें चुनावी जीत का मंत्र देंगे और उनमें उत्साह भरेंगे। कुछ रिपोर्टों के अनुसार, इस दिन वे कोलकाता के कुछ ऐतिहासिक स्थलों का भी दौरा कर सकते हैं।

दिल्ली में मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता पीएम मोदी ने की

नई दिल्ली, – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी दिल्ली में मुख्य सचिवों के पांचवें राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की, जिसमें केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन का मुख्य विषय "विकसित भारत के लिए मानव पूंजी" रखा गया, जिसमें शिक्षा, कौशल विकास, उच्च शिक्षा, खेल तथा बाल्यावस्था के सर्वांगीण विकास पर विशेष चर्चा हुई।

सम्मेलन का उद्देश्य केंद्र-राज्य साझेदारी को मजबूत करना, शासन सुधारों पर विचार-विमर्श करना और एक साझा राष्ट्रीय विकास एजेंडा तैयार करना था। इसमें नीति आयोग, केंद्रीय विभागों और विशेषज्ञों के साथ मिलकर बेहतर रणनीतियों और श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों पर बहस हुई।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि योजनाओं और नीतियों के समन्वय से नागरिकों की क्षमताओं को बढ़ाया जा सकता है और मानव पूंजी को देश की विकास शक्ति में परिवर्तित किया जा सकता है। सम्मेलन में डी-रेगुलेशन, शासन में तकनीक के उपयोग तथा आत्मनिर्भर भारत जैसे विषयों पर भी गहन विमर्श हुआ।

नेतन्याहू की अमेरिका यात्रा: ट्रंप से गाजा और क्षेत्रीय मुद्दों पर अहम वार्ता

संवाददाता |

नई दिल्ली/दुनिया, 28 दिसंबर 2025 – इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेटन्याहू रविवार को अमेरिका के लिए रवाना होंगे और सोमवार को फ्लोरिडा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। यह वर्ष 2025 में ट्रंप से नेतन्याहू की पाँचवीं बैठक होगी, जो इस वर्ष उनके बीच जारी कूटनीतिक संपर्क को दर्शाता है।

इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य गाजा पट्टी में 10 अक्तूबर को हुए युद्धविराम की अगली चरण योजना पर चर्चा करना है, जिसमें दूसरे चरण में हमास का निरस्त्रीकरण, अंतरिम फिलिस्तीनी सरकार की स्थापना, और अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल की तैनाती शामिल हैं।

साथ ही मुलाकात में ईरान के परमाणु कार्यक्रम, लेबनान में हिज़बुल्लाह की स्थिति और सुरक्षा समझौते पर भी बातचीत होने की संभावना है। अमेरिकी प्रशासन मध्यस्थों के साथ मिलकर इस विवादित संघर्ष विराम को मजबूत करने और शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। विश्लेषकों के अनुसार इस मीटिंग का क्षेत्रीय स्थिरता और मध्य पूर्व में शांति प्रयासों पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है और यह इजरायल-अमेरिका संबंधों की दिशा को भी आगे परिभाषित करेगा।

उन्नाव दुष्कर्म मामला: सुप्रीम कोर्ट कल हाईकोर्ट की सेंगर राहत पर करेगा सुनवाई

नई दिल्ली, 28 दिसंबर 2025 – सुप्रीम कोर्ट सोमवार, 29 दिसंबर को उन्नाव रेप मामले में विशेष सुनवाई करेगा, जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की याचिका पर निर्णय होना है। इस याचिका में CBI ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें **पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद सजा को निलंबित कर उन्हें जमानत दिए जाने का फैसला शामिल है। CBI का कहना है कि इस मामले में गंभीर अपराध और पीड़िता की सुरक्षा को देखते हुए सजा निलंबित करना गलत था और इसे चुनौती दी जानी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट की तीन न्यायाधीशीय वेकेशन बेंच का नेतृत्व मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत करेंगे और अन्य जस्टिस जे.के. माहेश्वरी तथा ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह भी इस बेंच में शामिल होंगे।

यह सुनवाई उस फैसले के खिलाफ है जिसमें 2017 के उन्नाव रेप केस में सेंगर को मिली उम्रकैद की सजा को कुछ शर्तों के साथ रोका गया और उन्हें राहत दी गई थी। CBI की अपील में दावा किया गया है कि बलात्कार जैसे संगीन अपराध में न्यायिक सहानुभूति दुर्लभ परिस्थितियों में ही दी जानी चाहिए, और उच्च न्यायालय के फैसले से पीड़िता और कानून की प्रतिष्ठा पर असर पड़ा है। आगामी सुनवाई इस उच्च-स्तरीय कांड के न्यायिक परिणाम को निर्णायक रूप से प्रभावित कर सकती है।

बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक दांव: हुमायूं कबीर की पार्टी 182 सीटों पर उतरेगी चुनाव

कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल और गरमाता दिख रहा है। निलंबित तृणमूल कांग्रेस विधायक हुमायूं कबीर ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी जनता उन्नयन पार्टी (JUP) की घोषणा करते हुए कहा है कि उनकी पार्टी राज्य की 294 विधानसभा सीटों में से 182 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यह कदम बंगाल की राजनीतिक सत्ता पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है और यह घोषणा चुनावी रणनीति को नया रूप दे रही है।

हुमायूं कबीर ने स्पष्ट किया है कि उनका मुख्य लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को सत्ता में आने से रोकना है। उन्होंने कहा कि आईएसएफ (Indian Secular Front) और एआईएमआईएम (AIMIM) के साथ संभावित गठबंधन की बातचीत के लिए तैयार हैं, जबकि इन दलों की ओर से अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है।

पहले कबीर ने कहा था कि उनकी पार्टी 135 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कम से कम 90 सीटें जीतने का लक्ष्य रखेगी, लेकिन रणनीति में बदलाव करते हुए यह संख्या बढ़ा दी गई है। उन्होंने दावा किया है कि 182 सीटों पर चुनाव लड़ने का नतीजा बहुत खास होगा, जो अनुभवी नेताओं के लिए भी चुनौती साबित होगा।

कबीर ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने मुस्लिम समुदाय के साथ विश्वासघात किया है, खासकर वक्फ़ (Waqf Act) से जुड़े मामलों में। उन्होंने घोषणाओं के साथ यह भी कहा कि गठबंधन की अंतिम रूपरेखा 31 दिसंबर तक तय कर ली जाएगी और इसके बाद सीटों के वाटप की रणनीति स्पष्ट होगी। राजनीति विश्लेषकों के अनुसार, हुमायूं कबीर का यह बड़ा दांव बंगाल की राजनीति में नया मतदाता समीकरण बना सकता है, जिससे मुख्य दलों के बीच टक्कर और तीव्र होगी। भाजपा, तृणमूल कांग्रेस और अन्य प्रमुख पार्टियों के लिए यह नई चुनौती सामने आ रही है, जो आगामी चुनाव के नतीजों पर स्पष्ट असर डाल सकती है।

इंदौर में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के विरोध में प्रदर्शन, यूनुस का पुतला जलाया

इंदौर: बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रही कथित हिंसा और अत्याचारों के विरोध में इंदौर में एक बड़ा जनआक्रोश प्रदर्शन आयोजित किया गया। प्रदर्शन की नेतृत्व भाजपा के पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय ने किया, जिसमें protestors ने बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का पुतला दहन किया और कड़े नारे लगाए। यह रैली बड़ा गणपति चौक से राजवाड़ा तक चली, जहाँ भारी संख्या में लोग शामिल हुए।

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के साथ जमकर हिंसा हो रही है और इसके खिलाफ भारतीय लोगों में गहरा रोष है। वे सरकार से मांग कर रहे हैं कि ऐसे देशों और व्यवस्थाओं के प्रति कड़ा रुख अपनाया जाए, जहाँ धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाता है। कई ने यह भी कहा कि भारत में भी मानवाधिकारों की रक्षा और अन्य देशों में रह रहे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के मुद्दे को विश्व स्तर पर उठाना चाहिए।

इसी तरह के विरोध प्रदर्शन देश के अन्य हिस्सों में भी देखने को मिले हैं, जहां हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश की नीतियों और वहां हो रही कथित हिंसा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इन प्रदर्शनों में विभिन्न स्थानों पर यूनुस का पुतला जलाया गया और विरोध के स्वर बुलंद किए गए हैं।

प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की बढ़ती घटनाओं ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता पैदा की है, जिससे भारत समेत अन्य देशों में भी यह मुद्दा जोर पकड़ रहा है। इस विरोध से यह स्पष्ट है कि बांग्लादेश में हिंसा के ख़िलाफ़ भावनाएँ भारत में भी बढ़ रही हैं और राजनीतिक तथा सामाजिक समूह इसे सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों के मुद्दे के रूप में उठा रहे हैं।

राजस्थान में बुर्का/घूंघट पहनकर वोट नहीं दे सकेंगी महिलाएँ: नई चुनाव गाइडलाइन जारी

जयपुर: राजस्थान में पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनावों से पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने एक अहम निर्देश (गाइडलाइन) जारी किया है, जिसके तहत बुर्का या घूंघट पहनकर मतदान केंद्र पर आने वाली महिलाओं को अपना चेहरा वोट डालने से पहले हटाना होगा ताकि उनकी पहचान सत्यापित की जा सके। मतदानकर्मियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी महिला अपने चेहरे को ढँककर वोट न डाले।

निर्देश के अनुसार, मतदान के दौरान पहचान के समय मतदाता को अपना आईडी कार्ड दिखाना आवश्यक होगा और चेहरा स्पष्ट रूप से पहचान के लिए दिखाना पड़ेगा। यह कदम मतदान प्रक्रिया की पारदर्शिता और सही पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय महिला कर्मचारियों की मदद भी ली जा सकती है, ताकि पर्दानशीं मतदाताओं की पहचान सम्मानजनक तरीके से की जा सके।

राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह नियम केवल पहचान सत्यापन के समय लागू होगा और इसका उद्देश्य निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं सुगम बनाना है। इससे किसी भी प्रकार की फर्जी वोटिंग और पहचान को लेकर विवाद को रोकने में मदद मिलेगी।

राजस्थान में यह नया निर्देश उन घोषणाओं के बीच आया है जब स्थानीय चुनाव को लेकर मतदाता सूची अद्यतन और गहन प्रक्रिया चल रही है, जिससे चुनावी प्रक्रिया को और अधिक सटीक बनाया जा रहा है। यह निर्णय निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ाने के प्रयास में लिया गया है, ताकि सभी मतदाता सही और सत्यापित मतदान कर सकें।

ग्रामीण रोज़गार पर संवाद ज़रूरी, टकराव नहीं

संपादकीय... |

देश में आज, 27 दिसंबर 2025, ग्रामीण रोज़गार व्यवस्था से जुड़े प्रस्तावित बदलावों को लेकर व्यापक चर्चा चल रही है। केंद्र सरकार की ओर से यह संकेत दिए गए हैं कि ग्रामीण आजीविका योजनाओं को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और दीर्घकालिक बनाने के लिए कुछ नीतिगत सुधार किए जा सकते हैं। इसी को लेकर राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और विशेषज्ञों के बीच विचार-विमर्श तेज़ हो गया है। (पीटीआई, एएनआई)

ग्रामीण भारत के लिए रोज़गार योजनाएँ केवल आय का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा का मजबूत आधार रही हैं। सूखा, बाढ़, महंगाई और कृषि संकट जैसे हालात में इन्हीं योजनाओं ने करोड़ों परिवारों को सहारा दिया है। ऐसे में यह स्वाभाविक है कि जब भी इनमें बदलाव की बात आती है, तो चिंताएँ और सवाल सामने आते हैं। (द हिंदू)

सरकार का दृष्टिकोण

केंद्र सरकार का कहना है कि प्रस्तावित सुधारों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को केवल “काम के दिन” तक सीमित न रखकर, स्थायी परिसंपत्तियों, कौशल विकास और स्थानीय आवश्यकताओं से जोड़ना है। सरकार यह भी मानती है कि बीते वर्षों में कुछ जगहों पर भुगतान में देरी, काम की गुणवत्ता और निगरानी को लेकर समस्याएँ सामने आई हैं। नई व्यवस्था इन कमियों को दूर करने की दिशा में एक प्रयास हो सकती है। (एएनआई)

सरकारी पक्ष के अनुसार, डिजिटल निगरानी और बेहतर योजना क्रियान्वयन से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि संसाधनों का सही उपयोग भी संभव होगा। यह तर्क नीतिगत दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी जनकल्याणकारी योजना की सफलता उसके क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। (पीटीआई)

विपक्ष और समाज की चिंताएँ

दूसरी ओर, विपक्षी दलों और कई सामाजिक संगठनों की चिंता यह है कि कहीं सुधारों के नाम पर रोज़गार की गारंटी कमजोर न पड़ जाए। उनका कहना है कि ग्रामीण इलाकों में आज भी बड़ी आबादी ऐसी है, जिसके लिए यह योजना न्यूनतम आय और सम्मानजनक जीवन का आधार है। (इंडियन एक्सप्रेस)

विपक्ष का यह भी तर्क है कि किसी भी बदलाव से पहले राज्यों, पंचायतों और ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले संगठनों से विस्तृत परामर्श होना चाहिए। ग्रामीण भारत की विविधता को देखते हुए एक समान नीति हर क्षेत्र में समान रूप से कारगर होगी, यह मान लेना व्यावहारिक नहीं होगा। (पीटीआई)

ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

विशेषज्ञों का मानना है कि ग्रामीण रोजगार योजनाएँ कृषि के बाहर आय के अवसर पैदा करती हैं और पलायन को रोकने में भी मददगार रही हैं। यदि सुधारों से काम की गुणवत्ता और समय पर भुगतान सुनिश्चित होता है, तो यह सकारात्मक परिणाम दे सकता है। लेकिन यदि ज़मीनी क्रियान्वयन कमजोर रहा, तो इससे असंतोष और अनिश्चितता बढ़ सकती है। (द हिंदू)

इसलिए यह आवश्यक है कि किसी भी नई व्यवस्था में काम के दिनों, मजदूरी दर और भुगतान की समयसीमा को लेकर स्पष्टता बनी रहे। भरोसा तभी बनेगा, जब लाभार्थियों को यह महसूस हो कि उनकी सुरक्षा पहले जैसी ही मज़बूत है। (इंडियन एक्सप्रेस)

संवाद की आवश्यकता

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह विषय टकराव का नहीं, बल्कि संवाद और सहमति का है। सरकार के लिए भी यह ज़रूरी है कि वह सुधारों के लाभों को स्पष्ट रूप से सामने रखे और आशंकाओं का समाधान करे। वहीं विपक्ष की भूमिका भी केवल विरोध तक सीमित न रहकर रचनात्मक सुझाव देने की होनी चाहिए। (एएनआई)

ग्रामीण भारत की अपेक्षा केवल घोषणाओं से पूरी नहीं होगी। ज़रूरत है ज़मीनी सच्चाई को समझते हुए ऐसी नीतियाँ बनाने की, जो स्थिरता, सम्मान और आत्मनिर्भरता का भरोसा दें।

निष्कर्ष

ग्रामीण रोज़गार पर चल रही यह बहस लोकतंत्र की सेहत के लिए महत्वपूर्ण है। सुधार समय की मांग हो सकते हैं, लेकिन उन्हें विश्वास, पारदर्शिता और सहभागिता के साथ लागू करना ही समझदारी होगी। सरकार और विपक्ष—दोनों को यह याद रखना चाहिए कि इस नीति के केंद्र में कोई आंकड़ा नहीं, बल्कि करोड़ों ग्रामीण परिवारों का भविष्य है।

यदि संवाद और संतुलन के साथ आगे बढ़ा गया, तो यह बहस ग्रामीण भारत को और सशक्त बनाने का अवसर बन सकती है।

WORLD NEWS | पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने उगला जहर

मोदी को पता चल गया कि हम जंग को तैयार... पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने उगला जहर, बोले- चार दिन तुम्हारी टांगें न खड़ी हो सकीं

इस्लामाबाद | पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने अपनी पत्नी बेनजीर भुट्टो की पुण्यतिथि पर जमकर जहर उगला है। उन्होंने मई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान को रोटी खाने वाली नसीहत पर भी टिप्पणी की। जरदारी ने मई में हुए भारत-पाकिस्तान संघर्ष का जिक्र करते हुए भारत को गीदड़भभकी भी दी। उन्होंने शेखी बघारते हुए कहा कि चार दिनों तक भारत की टांगें खड़ी नहीं हो सकी। जबकि, पूरी दुनिया ने देखा कि भारतीय मिसाइलों और ड्रोन ने पाकिस्तान को कैसे तबाह किया था। इस दौरान पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह हुए, कम से कम 5 लड़ाकू विमान नष्ट हुए और 100 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों की भी मौत हुई थी।

भारत को मुंहतोड़ जवाब मिला

जरदारी ने कराची में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, "... मुझसे आकर कहा कि सर!जंग शुरू हो गई है। वैसे तो मैंने उसको चार दिन पहले बोला था कि जंग होने वाली है। मगर उसने मुझे आकर कहा कि सर, वो बंकर में चलें। मैने कहा कि शहादत आनी है तो यहीं आएगी। बंकरों में नहीं मरते लीडर, मैदानों में मरते। यहां नहीं मरते, बंकरों में बैठ के। फौज ने आंखों में आंखें डाल के, हमारी सरकार की देखरेख में भारत को ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया कि उनको पता पड़ गया कि ये ... नहीं हैं।"

पीएम मोदी के बयान पर गीदड़भभकी

उन्होंने आगे कहा, "मोदी को पता पड़ गया कि ये सब वर्कर (पीपीपी कार्यकर्ता) जंग के मैदान के लिए खुद तैयार हैं। हम खुद हथियार लेकर लड़ने के लिए तैयार हैं। हम अपनी जानों की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। इस मुल्क को बचाने के लिए तैयार हैं। ये भूल जाओ कि "रोटी होगी-गोली होगी। रोटी होगी गोली होगी"।

हम गोलियां मारेंगे, तुम क्या गोली मारोगे। तुमने देखा कि चार दिन तुम्हारी टांगें खड़ी नहीं हो सकीं। चार दिन तुम जंग नहीं कर सके। इतनी बड़ी इकॉनमी, 10 गुना हमसे बड़ा मुल्क अपने को कहलाते हो। मगर वो दिल-गुर्दा कहां से लाओगे।"

जरदारी ने मुनीर की तारीफ की

जरदारी ने कहा, "हम जंग के शौकीन नहीं हैं। हम किसी मुल्क से लड़ना नहीं चाहते। मगर कोई हमारी गिरेबान में हाथ डालेगा, तो हम उसको थोबी पछाड़ मारेंगे, जिस तरह हमने इंडिया को मारा था। अब इनको भी मारेंगे। जो भी हमारी धरती की तरफ नासूर आंखों से देखेगा, तो हमारा ऐसा चीफ बैठा है, जो उनको चने चबा देगा। पाकिस्तान की आर्मी उनको चने चबा देगी और एयरफोर्स चने चबा देगी। हमारी नेवी चबा देगी। ये सब बीबी साहिबा (बेनजीर भुट्टो) और हमने पहले से बंदोबस्त करके रखे हैं। भुट्टो साहब (जुल्फिकार अली भुट्टो) से लेके आजतक हम इसकी तैयारी करके बैठे हैं कि हो सकता है कि कभी हमारी जरूरत पड़ जाए।"

F-35 News: अमेरिका के लिए सिरदर्द क्यों बना F-35 लड़ाकू विमान, पेंटागन की ऑडिट में चौंकाने वाले खुलासे

अमेरिकी F-35 प्रोग्राम को लेकर पेंटागन की ऑडिट रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए हैं। इनमें बताया गया है कि F-35 प्रोग्राम कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है। इस कारण न सिर्फ इसकी लागत बढ़ रही है, बल्कि इस प्रोग्राम में शामिल देश भी दूसरे लड़ाकू विमानों को खरीदने की योजना बना रहे हैं।

वॉशिंगटन: अमेरिकी वायुसेना के F-35 लड़ाकू विमानों को लेकर पेंटागन की ऑडिट में चौंकाने वाले खुलासे हुए है। इन खुलासों ने F-35 बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन की नींद उड़ा दी है। इस ऑडिट में पता चला है कि F-35 विश्वसनीयता, लागत और राजनीतिक मिशनों को अंजाम देने में नाकाम रहा है। इस कारण यूरोप और एशिया के कई देश F-35 की जगह यूरोफाइटर टाइफून, राफेल और ग्रिपेन जैसे विकल्पों की ओर देख रहे हैं। इसके अलावा ये देश खुद के लड़ाकू विमानों को बनाने पर भी जोर दे रहे हैं, जिसका सीधा असर अमेरिकी रक्षा बाजार पर पड़ रहा है।

ऑडिट रिपोर्ट में क्या कहा गया

ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि DoD जॉइंट स्ट्राइक फाइटर (JSF) अपनी अत्यधिक तकनीकी जटिलता, एक ही डिजाइन से तीन अत्यधिक विशिष्ट विमान वेरिएंट बनाने के लक्ष्य, महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला और विनिर्माण मुद्दों, और लगातार सॉफ्टवेयर अपडेट समस्याओं के कारण धीमा रहा है। JSF प्रोग्राम नौ देशों (संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, इटली, नीदरलैंड, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, नॉर्वे) के बीच एक संयुक्त प्रयास है, जिनमें से प्रत्येक इस प्रोग्राम से निश्चित संख्या में विमान खरीदने की योजना बना रहा है। हालांकि, जुलाई 2019 में, रूस के S-400 मिसाइल सिस्टम को खरीदने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने तुर्की को सहयोगियों की सूची से हटा दिया था। तुर्की ने शुरू में इस प्रोग्राम के माध्यम से लगभग 100 JSF खरीदने की योजना बनाई थी।

F-35 के वेरिएंट ने बढ़ी परेशानी

ऑडिट में यह भी कहा गया है कि F-35 को समय पर डेवलप करने में मुख्य चुनौती एक ही एयरक्राफ्ट फ्रेम को तीन अलग-अलग सैन्य जरूरतों के लिए डिजाइन करना रहा है। दरअसल, F-35 के तीन वेरिएंट बनाए जाते हैं, जिनमें से पहला- पारंपरिक टेकऑफ यानी F-35A, दूसरा- शॉर्ट टेकऑफ/वर्टिकल लैंडिंग यानी मरीन कॉर्प्स के लिए F-35B और तीसरा- कैरियर बेस्ड ऑपरेशन यानी अमेरिकी नौसेना के लिए F-35C) हैं। हर वेरिएंट को बनाने में न सिर्फ डिजाइन बल्कि तकनीकी रूप से भी कई समझौते करने पड़े हैं। इस कारण इनके निर्माण में कई चुनौतियां पैदा हुई हैं।

सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ने बढ़ाई टेंशन

रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि F-35 का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को भी एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है। मौजूदा टेक्नोलॉजी रिफ्रेश 3 (TR-3) को अपग्रेड किया जा रहा है कि ताकि ब्लॉक-4 विमानों का निर्मण किया जा सके। इसमें बहुत ज्यादा समय लग रहा है। इसके अलावा F-35 प्रोग्राम में शामिल कॉन्ट्रैक्टर्स इंजन और एयरक्राफ्ट की डिलीवरी में देरी कर रहे हैं। इनके अलावा मैन्युफैक्चरिंग की समस्याएं और पार्ट्स की कमी का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि बड़ी संख्या में F-35 लड़ाकू विमानों को उनके कुछ कंपोनेंट्स के न होने कारण फाइनल ऑपरेशन सर्टिफिकेट (FOC) नहीं मिल पा रहा है।

F-35 की डिलीवरी में 8 महीने की देरी

इससे पहले अमेरिकी सरकारी लेखा कार्यालय (GAO) की 3 सितंबर की जारी रिपोर्ट में बताया गया था कि F-35 लड़ाकू विमान का निर्माण करने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन और इंजन बनाने वाली कंपनी प्रैट एंड व्हिटनी तय समय पर डिलीवरी देने में नाकाम रही हैं। 2023 में इन दोनों कंपनियों से डिलीवर किए गए F-35 लड़ाकू विमान तय समय से औसतन 61 दिनों की देरी से पहुंचे। 2024 में, यह समस्या और ज्यादा बढ़ गई। इस साल डिलीवर किया गया हर F-35 औसतन 238 दिनों की देरी से पहुंचा।

F-35 की टेक्नोलॉजी रिफ्रेश बनी परेशानी

रिपोर्ट में देरी का मुख्य कारण टेक्नोलॉजी रिफ्रेश 3 (TR-3) को बताया गया है। यह F-35 के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अपग्रेड का एक सेट है, जिसकी मदद से अमेरिका अपने 2 बिलियन डॉलर के "ब्लॉक 4 अपग्रेडेशन" को अंजाम दे रहा है। ऐसे में अमेरिकी ऑडिटर्स को आशंका है कि F-35 प्रोग्राम की लागत पहले की तय योजना से लगभग 6 बिलियन डॉलर अधिक होगी। इतना ही नहीं, अब यह प्रोग्राम शुरू में अनुमानित समय से कम से कम पांच साल बाद पूरा होगा। GAO की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी रक्षा विभाग ने समय पर डिलीवरी में सुधार के लिए कॉन्ट्रैक्टरों को लाखों डॉलर की प्रोत्साहन फीस भी दी है।

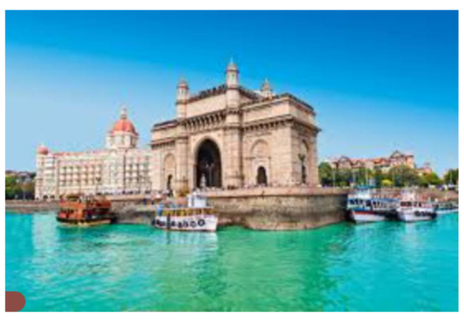

महाराष्ट्र विशेष

कोकण > पश्चिम महाराष्ट्र > मराठवाड़ा > विदर्भ

भाजपा के सहारे नांदेड में "मजपा" की एंट्री!

नांदेड (27 दिसंबर 2025) – नगर पालिका चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मराठवाडा जनहित पार्टी (मजपा) को सहयोगी के रूप में मैदान में उतारने की रणनीति अपनाई है। भाजपा के लिए कठिन प्रभागों में जहां खुद के उम्मीदवारों के जीतने की संभावना कम है, वहां मजपा के उम्मीदवारों को भाजपा का समर्थन देने की तैयारी चल रही है।

धर्माबाद नगर परिषद में मजपा ने पहले ही अपने दम पर जीत दर्ज की है और भोकर नगर परिषद में भी उसके चार नगरसेवक चुने गए हैं। भाजपा के स्थानीय नेतृत्व और राज्य प्रभारी चंद्रशेखर बावनकुले के बीच चुनावी समीकरणों पर बैठकों के बाद यह निर्णय लिया गया है। मजपा के कुछ उम्मीदवारों को भाजपा के चिन्ह "कपबशी" पर भी मैदान में उतारने की चर्चा है। इससे स्पष्ट है कि भाजपा कठिन इलाकों में अपने प्रदर्शन को मजबूत करने के लिए क्षेत्रीय दलों के साथ सहयोग को बढ़ावा दे रही है।

शरद पवार एनडीए में होंगे शामिल... एकनाथ शिंदे के मंत्री संजय शिरसाट का बड़ा दावा, महाराष्ट्र में हलचल तेज

मुंबई | महाराष्ट्र की कई नगर निगमों में गठबंधन के लिए शरद पवार की एनसीपी अजीत पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी गुट से बातचीत कर रही है, जिससे विपक्षी खेमे में बेचैनी बढ़ गई है। शिवसेना (एकनाथ शिंदे) के मंत्री संजय शिरसाट ने दावा किया है कि यह कदम शरद पवार के अंततः एनडीए में शामिल होने का संकेत है। शिरसाट ने कहा कि आने वाले समय में शरद पवार के एनडीए में शामिल होने की संभावना है। क्या किसी ने सोचा था कि वे उद्धव ठाकरे के साथ हाथ मिलाएंगे? लेकिन उन्होंने ऐसा किया और वे ढाई साल तक सत्ता में रहे। उन्होंने सोनिया गांधी का विरोध किया और कांग्रेस छोड़ दी, फिर तुरंत उनके साथ गठबंधन कर लिया। अगर वे एनडीए में शामिल होते हैं तो यह आश्चर्य की बात नहीं होगी। अगर आप राजनीति का अध्ययन करें तो यह उनका राजनीतिक करियर रहा है।

संजय शिरसाट के इस बयान से एनसीपी (एसपी) के अगले कदमों को लेकर और भी सवाल खड़े हो गए हैं। वर्तमान में पुणे और पिंपरी-चिंचवाड़ नगर निगमों में गठबंधन के लिए अजीत पवार गुट से बातचीत कर रही है।

शरद पवार की पार्टी से आई सफाई

उद्धव बालासाहेब ठाकरे की सेना और कांग्रेस के नेता एनसीपी (एसपी) द्वारा राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर भाजपा के साथ गठबंधन वाली पार्टी के साथ संबंध स्थापित करने से नाखुश हैं। हालांकि, एनसीपी (एसपी) ने शिरसाट की टिप्पणियों को खारिज कर दिया। पार्टी नेता जयंत पाटिल ने कहा कि यह हमारी ईमानदारी पर संदेह पैदा करने का प्रयास है। उन्होंने आगे कहा कि इन टिप्पणियों को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए।

क्या बोले जयंत पाटिल

महत्वपूर्ण बात यह है कि पाटिल ने यह भी पुष्टि की कि एनसीपी (एसपी) मुंबई नगर निगम चुनावों के लिए यूबीटी सेना-एमएनएस गठबंधन और कांग्रेस दोनों के साथ समानांतर बातचीत कर रही है। उन्होंने कहा कि हां, हमारे दो प्रतिनिधिमंडल हैं। एक कांग्रेस से सीट बंटवारे पर बात कर रहा है और दूसरा मुंबई नगर निगम चुनावों के लिए यूबीटी सेना-एमएनएस के साथ चर्चा कर रहा है। जयंत पाटिल ने पुणे और पिंपरी-चिंचवाड़ में अजीत पवार गुट के साथ पार्टी की बातचीत का बचाव किया। उन्होंने कहा कि नगर निकायों में कांग्रेस और शिवसेना के साथ जाना हमारी प्राथमिकता रही है। हालांकि, इन दोनों निगमों में जब हम एकजुट थे तब हमारे पास अधिक पार्षद थे। इसलिए, हम वहां गठबंधन की संभावना का आकलन कर रहे हैं।

बॉम्बे हाईकोर्ट का साफ़ आदेश: भारत रत्न-पद्म पुरस्कार नाम के आगे/पीछे उपाधि नहीं हो सकते

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्देश में स्पष्ट किया है कि भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे नागरिक सम्मान कानूनी "टाइटल" नहीं हैं और इन्हें किसी व्यक्ति के नाम के आगे (prefix) या पीछे (suffix) नहीं जोड़ा जाना चाहिए। अदालत ने यह टिप्पणी एक याचिका की सुनवाई के दौरान दी, जिसमें सुनवाई के शीर्षक में पद्म पुरस्कार का उपयोग "पद्मश्री डॉ. शरद एम. हार्डिकर" के रूप में किया गया था। हाईकोर्ट ने मामला रिकॉर्ड से यह उपसर्ग हटाने का आदेश दिया।

न्यायमूर्ति सोमसेखर सुंदरेशन ने कहा कि ये पुरस्कार राष्ट्रीय सम्मान के प्रतीक हैं, लेकिन अधिकारिक उपाधियों की तरह नहीं माने जा सकते और उनका इस तरह उपयोग कानून और संविधान के खिलाफ है। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के 1995 के फैसला का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि ये पुरस्कार "टाइटल" नहीं हैं और Article 18(1) के तहत किसी नाम के साथ जोड़े नहीं जा सकते।

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि सभी अदालतों और पक्षों को इस कानून का पालन करना चाहिए और नामों में इन पुरस्कारों का इस्तेमाल करना रोकना आवश्यक है। यह आदेश नागरिक सम्मानों की गरिमा बनाए रखने और उन्हें कानूनी उपाधियों से अलग रखने के प्रयास का हिस्सा माना जा रहा है।

छत्रपती संभाजीनगर में एमआईएम कार्यकर्ताओं के बीच उमेदवारी को लेकर झड़प, मामला पुलिस स्टेशन तक पहुँचा

छत्रपती संभाजीनगर में निकाय चुनाव 2026 को लेकर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इ-त्तेहादुल मुस्लिमीन (एमआईएम) पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोरदार विवाद और हंगामा देखने को मिला। पार्टी ने वार्ड नंबर 12 के लिए मोहम्मद इसरार को अपना अधिकृत उम्मीदवार घोषित किया था। इस घोषणा के बाद शुक्रवार शाम किराडपुरा इलाके में इसरार के समर्थकों ने एक रैली निकाली। इसी दौरान टिकट न मिलने से नाराज़ एक अन्य गुट, जिसमें हाजी इसाक के समर्थक थे, रैली के रास्ते में पहुंच गए और उम्मीदवार की रैली को रोकने का प्रयास किया। दोनों पक्षों के बीच शब्दों का विवाद जल्दी ही भड़क剩 ता हाथापाई में बदल गया, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस को बुलाना पड़ा और पथरांव तथा संघर्ष से स्थिति को नियंत्रित किया गया। घटना के बाद जिन्सी पुलिस थाना में दोनों पक्षों के कार्यकर्ता पहुँचे और मारपीट की शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस ने मारपीट में शामिल कुछ लोगों के खिलाफ अदखलपात्र मामला दर्ज किया है, लेकिन दूसरी तरफ से शिकायत नहीं दर्ज करवाई गई है। इस विवाद ने एमआईएम के भीतर उमेदवारी वितरण को लेकर चल रही असंतोष को उजागर किया, जहां पार्टी संगठन के फैसले से कई पार्टी कार्यकर्ता नाराज़ बताए जा रहे हैं। मामला क्षेत्र में चुनावी राजनीति की आंतरिक जटिलताओं और संघर्ष को दर्शाता है।

मुंबई BMC चुनाव: बाला नांदगावकर बोले—ठाकरे-मनसे युति में सीट-वाटप पर अभी मतभेद जारी

संवाददाता |

मुंबई: आगामी मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनाव 2026 के लिए शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट-UBT) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) ने गठबंधन की घोषणा तो कर दी है, लेकिन सीट-वाटप (seat sharing) को लेकर दोनों पक्षों में सहमति अभी भी स्पष्ट नहीं है। भाजपा-शिंदे गुट की महायुति को टक्कर देने के लिए यह युति राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है, लेकिन सीटों के बंटवारे पर चर्चा जारी है।

मनसे के वरिष्ठ नेता बाला नांदगावकर ने मीडिया से कहा कि "कुछ वार्डों में आदलाबदल (देवाण-घेवाण) पर चर्चा चल रही है" और अंतिम निर्णय के बाद ही सीट-वाटप का फॉर्मूला घोषित किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि उद्धव ठाकरे के साथ मातोश्री में हुई बैठक में इस मुद्दे पर विचार किया गया, और राज ठाकरे के साथ आगे की बातचीत भी तय है।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यद्यपि गठबंधन घोषित हो चुका है, सीटों के बंटवारे का ठोस फॉर्मूला अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, जिससे दोनों दलों के बीच हल्की खींचतान देखने को मिल रही है। मुंबई जैसे बड़े निकाय चुनाव में इस तरह के मतभेद का असर प्रत्याशियों के चयन और मतदाताओं की धारणा पर पड़ सकता है। यह चुनाव 15 जनवरी 2026 को होने वाला है, जिसमें कुल 227 सीटें हैं और बहुमत जोड़ने के लिए पार्टियों को रणनीति मजबूत करनी पड़ेगी।

घर में माता-पिता की लाशें, दोनों बच्चे के शव रेलवे ट्रैक पर, नांदेड़ में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, महाराष्ट्र हैरान

नांदेड़: महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई है। पुलिस की जांच में पता चला है कि दो भाइयों ने पहले अपने माता-पिता की गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर खुद ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी। यह भयानक कदम उन्होंने आर्थिक तंगी के कारण उठाया। इस मामले में बाराड़ पुलिस ने केस दर्ज जांच शुरू कर दी है।

असली मामला क्या है?

मुदखेड तहसील के ज्वाला मुरहर गांव में एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत का मामला गुरुवार सुबह 25 दिसंबर को सामने आया। इसमें रमेश सोनाजी लखे (51) और उनकी पत्नी राधाबाई लखे (45) घर में मृत पाए गए। जबकि उनके दो बेटों उमेश लाखे (उम्र 25) और बजरंग लाखे (उम्र 22) के शव गांव से कुछ दूरी पर मुगत रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर मिले। राधाबाई हमेशा सुबह पूजा के लिए मंदिर आती थीं, लेकिन जब उस दिन वह मंदिर नहीं आईं तो गांव की एक महिला उनके घर गई और घटना का पता चला।

सुसाइड था या मर्डर?

इस घटना के बाद यह सुसाइड था या मर्डर? इस पर बहस छिड़ गई। इस बीच चारों का पोस्टमॉर्टम किया गया। इसमें पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चला कि पति-पत्नी की मौत गला घोंटने से हुई थी। दोनों बच्चों ने पहले अपने माता-पिता का सोते हुए गला घोंटा, फिर दोनों अपने टू-व्हीलर से मुगत रेलवे स्टेशन पहुंचे और ट्रेन के नीचे कूदकर सुसाइड कर लिया। रमेश लाखे की फाइनेंशियल हालत खराब थी। रमेश लाखे को स्ट्रोक आया था और वह लगातार बीमार रहता था। इसी फाइनेंशियल तंगी के कारण बच्चों ने अपने माता-पिता को मार डाला और फिर खुद भी सुसाइड कर लिया।

'हम गांव बाहर जाना चाहते हैं'

खास बात यह है कि दोनों भाई उमेश और बजरंग किसी के कॉन्टैक्ट में नहीं थे। घटना के बाद दोनों भाई रात करीब 1:30 से 2:30 बजे मोटरसाइकिल पर अपने घर से निकले। उस समय उन्होंने गांव के पंतपारी ड्राइवर को जगाया और उससे सुपारी के पैकेट खरीदे थे। उन्होंने पंतपारी ड्राइवर से यह भी कहा कि वह अपने गांव बाहर जाना चाहता है। पुलिस ने उनसे इस बारे में पूछताछ की। इस बीच बाराड़ पुलिस ने इस मामले में भाई-बहन उमेश और बजरंग लाखे के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है।

हर समस्या का है हल

मन में सुसाइड का ख्याल आए तो मनोचिकित्सक से बात करके आप अपनी समस्या का हल खोज सकते हैं। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 14416 है, जहां आप 24X7 संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई हेल्पलाइन नंबर्स हैं जहां आप संपर्क कर सकते हैं। सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन- 1800-599-0019 (13 भाषाओं में है) इंस्टीट्यूट ऑफ़ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज-9868396824, 9868396841, 011-22574820 हितगुज हेल्पलाइन, मुंबई- 022-24131212 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस-080 - 26995000

परभणी में महाविकास आघाड़ी की संभावित ताकत: सांसद संजय जाधव और विधायक राहुल पाटील की महत्वपूर्ण बैठक

परभणी: आगामी महानगरपालिका चुनाव 2026 के मद्देनज़र परभणी में राजनीतिक परिदृश्य में जबरदस्त बदलाव देखने को मिल रहा है। भाजपा-शिंदेसेना महायुति गठबंधन की सक्रियता के बीच अब महाविकास आघाड़ी (MVA) की भी भूमिका मजबूत होती दिख रही है। परभणी में सांसद संजय जाधव और विधायक डॉ. राहुल पाटील के बीच हाल ही में हुई बैठक ने राजनीतिक हलचल को और तेज कर दिया है। इस मुलाकात को महाविकास आघाड़ी के दरवाज़े खुलने जैसा करार दिया जा रहा है, जिससे आघाड़ी के तहत चुनाव लड़ने की संभावनाएँ बढ़ती दिख रही हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक पिछले डेढ़ दशक में परभणी शहर में सत्ता समीकरण में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) और कांग्रेस का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार महायुति के दबाव के चलते अन्य दल भी सक्रिय हो गए हैं। इससे बड़ी चुनौती यह है कि यदि महाविकास आघाड़ी के तीनों प्रमुख घटक कांग्रेस, उद्धवसेना और राष्ट्रवादी (शरद पवार गुट) एक साथ चुनाव लड़ते हैं, तो भाजपा-शिंदेसेना को कड़ी टक्कर मिल सकती है।

बैठक में नेताओं ने महाविकास आघाड़ी के रूप में साझा रणनीति बनाने पर चर्चा की और गठबंधन के रास्ते को आसान बनाने के संकेत दिए। महाविकास आघाड़ी के लिए इच्छुक नेताओं और कार्यकर्ताओं की संख्या उल्लेखनीय है, जिससे मैदान पर उनकी चुनौती और बढ़ सकती है।

इस बीच भाजपा-शिंदेसेना तथा राष्ट्रवादी (अजित पवार गुट) अलग-अलग रणनीतियाँ बना रहे हैं, जिससे संभावित मत विभाजन का जोखिम भी बढ़ रहा है। हालांकि भाजपा-शिंदेसेना का महापालिका चुनाव में गठबंधन जारी रखने का निर्णय अभी अंतिम नहीं हुआ है, पर उससे जुड़े समीकरण पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर महाविकास आघाड़ी समय रहते गठबंधन को अंतिम रूप दे पाती है, तो यह परभणी महानगरपालिका चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकती है और सत्ता के समीकरण को बदल सकती है।

नांदेड़ वॉक्स

नांदेड़ जिला > नांदेड़ शहर

नंदिग्राम टाईम्स
RNI NO. MAHHIN/2016/69743 EDITOR : SHAIKH JAHUR AHEMAD
Sunday 28th December 2025 वर्ष - 9 , अंक 242 , पृष्ठ 04

आदित्य ठाकरे का तीखा हमला: "योगीजी, कोरोना-काल में उत्तर प्रदेश में क्यों पड़े मृत शरीर सड़कों पर?"

नाशिक से प्रकाशित, 27 दिसंबर 2025 – शिवसेना (उद्धव ठाकरे) के विधायक आदित्य ठाकरे ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कोरोना महामारी के दौरान हुई मौतों के प्रबंधन को लेकर कड़ी आलोचना की। ठाकरे ने कहा कि महामारी के समय उत्तर प्रदेश में मृतकों के शव सड़कों पर पड़े मिले और उनका दहन भी गम्भीर ढंग से नहीं हुआ, जबकि महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य ने बेहतर तरीके से कोरोना प्रबंधन किया। उन्होंने सीधे उठाकर पूछा, "योगीजी, तब प्रेत क्यों रस्त्यावर होते थे?" और योगी सरकार से उस दौर का विस्तृत हिसाब माँगा।

आदित्य ठाकरे का यह बयान नागरिक निकाय चुनाव प्रचार के दौरान आया है, जिसमें उन्होंने यूपी प्रशासन की तुलना महाराष्ट्र की कोरोना प्रतिक्रिया से कर प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। ठाकरे ने कहा कि अगर यूपी प्रशासन कोरोना के समय प्रभावी होता तो ऐसे दृश्य सामने नहीं आते। अख़बारों में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने योगी सरकार को स्पष्ट जवाब और गहन समीक्षा की मांग भी की है।

NANDED NEWS | नांदेड महापालिका चुनाव:

नांदेड महापालिका चुनाव: स्थानीय मतभेदों के बावजूद भाजपा-शिंदेसेना गठबंधन की दिशा मजबूत

नांदेड | नांदेड-वाघाळा महानगरपालिका निवडणूक (15 जनवरी 2026) के लिए राजनीतिक परिदृश्य में व्यापक बदलाव के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। राज्य स्तर पर चली महत्त्वपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों के बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) और **एकनाथ शिंदे नेतृत्व वाली शिंदेसेना के बीच चुनावी गठबंधन के पक्ष में हवा बनी हुई है, भले ही स्थानीय नेताओं के बीच मतभेद और असहमति मौजूद हो।

लोकमत की रिपोर्ट के अनुसार, नांदेड महापालिका की 81 सीटों पर हो रहे चुनावों को लेकर सभी बड़े दल सक्रिय हैं। भाजपा ने जोरदार प्रचार-प्रसार शुरू किया है, जबकि शिंदेसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार गुट) भी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। कांग्रेस पार्टी भी रवींद्र चव्हाण के नेतृत्व में कड़ा मुकाबला करने की तैयारी में है। फिलहाल सभी दल "स्वबळ" यानी अकेले चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक समीकरण आगामी दिनों में बदल सकते हैं।

राज्य स्तर के समीकरणों का प्रभाव स्थानीय राजनीति पर साफ़ दिखाई दे रहा है। स्थानीय नेतृत्व के मतभेद के बावजूद BJP-शिंदेसेना गठबंधन को अपरिहार्य माना जा रहा है, क्योंकि दोनों दल महायुति (Mahayuti) के तहत चुनावी रणनीति को मजबूत बनाना चाहते हैं। अगर यह गठबंधन तय होता है, तो सीटों का बंटवारा, उम्मीदवार चयन और क्षेत्रीय समीकरणों पर तीव्र चर्चाएँ और प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी। खासकर उन विकेन्द्रित वार्डों में, जहाँ मुस्लिम और दलित मतदाता की संख्या अधिक है, वहां यह निर्णय चुनावी परिणामों को निर्णायक रूप से प्रभावित कर सकता है। राजनीतिक तौर पर नांदेड में कुछ अन्य दलों और समूहों की भूमिका भी महत्वपूर्ण बनी हुई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के एक गुट का असर सीमित होने के बावजूद उनके स्थानीय समर्थकों की उपस्थिति से गठबंधन गणित में जटिलता बढ़ सकती है। वहीं, मराठवाडा जनहित पार्टी जैसी क्षेत्रीय ताकतों ने राय मुड़ते परिदृश्य में अलग पहचान बनाने के भी प्रयास किए हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा-शिंदेसेना गठबंधन के लिए कोई बड़ी कानूनी या संगठनात्मक बाधा नहीं है, और वरिष्ठ नेताओं द्वारा इससे जुड़े वार्तालाप भी सकारात्मक दिशा में चल रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और पार्टी शीर्ष नेतृत्व के बयान भी इस दिशा में संकेत दे रहे हैं कि महायुति स्थानीय निकाय चुनावों में एक साझा मंच से चुनाव लड़ सकती है, ताकि विपक्षी दलों के मुकाबले अधिक मजबूत स्थिति बनाई जा सके।

इस प्रकार नांदेड महापालिका चुनाव में स्थानीय मतभेदों के बावजूद बड़े राजनीतिक गठबंधनों की तैयारियाँ चल रही हैं, जो आगामी चुनाव परिणाम के समीकरणों को नया आकार दे सकती हैं।

हिंगोली पुलिस प्रशासन में गड़बड़ी: एक साथ दो पुलिस अधीक्षक, अधिकारी और कर्मचारियों में भारी भ्रम

हिंगोली (27 दिसंबर 2025) – जिले के पुलिस प्रशासन में असामान्य स्थिति उत्पन्न हो गई है, जहाँ दोपहर से एक ही समय पर दो पुलिस अधीक्षक मौजूद हैं। राज्य सरकार के गृह विभाग ने डॉ. श्रीकृष्ण कोकाटे की जगह डॉ. नीलाभ रोहन को नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया और उन्होंने 23 दिसंबर को पदभार भी ग्रहण किया। हालांकि, डॉ. कोकाटे ने इस बदली के खिलाफ केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) में याचिका दायर की और न्यायाधिकरण ने स्थगन आदेश दिया है, जिससे कोकाटे को हटाया नहीं जा सका।

इससे पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों में संभ्रम की हालत बनी हुई है कि किसके आदेशों का पालन करना है। दैनंदिन कार्य और आदेशों के क्रियान्वयन को लेकर स्पष्ट दिशा नहीं मिल पाने से हिंगोली के पुलिस बल में प्रशासनिक पेच बढ़ गया है। न्यायाधिकरण की अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी।

महानगरपालिका चुनाव: नामांकन के लिए केवल दो दिन शेष, राजनीतिक दलों में बगावत रोकने की रणनीति तेज

नांदेड | नांदेड-वाघाला शहर महानगरपालिका के 20 प्रभागों से 81 सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। 23 दिसंबर से नामांकन पत्र दाखिल करने की शुरुआत हो चुकी है और 30 दिसंबर नामांकन की अंतिम तिथि है। नामांकन के लिए अब केवल दो दिन शेष रहने के कारण राजनीतिक गतिविधियां चरम पर पहुंच गई हैं। हालांकि, प्रमुख राजनीतिक दलों ने अब तक अपने उम्मीदवारों की सूची सार्वजनिक नहीं की है। पार्टी नेतृत्व बगावत टालने के लिए पूरी सतर्कता बरत रहा है।

महानगरपालिका चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अंदरूनी तौर पर रणनीति तैयार कर ली है, लेकिन उम्मीदवारों के नामों को लेकर गोपनीयता बनाए रखी जा रही है। किसे टिकट मिलेगा, इसे लेकर सस्पेंस बरकरार रखा गया है। इससे इच्छुक उम्मीदवारों की बेचैनी बढ़ गई है।

सूत्रों के अनुसार, कई दलों ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी प्रकार की सिफारिश नहीं मानी जाएगी और सर्वेक्षण में जिनका नाम सबसे ऊपर आएगा, उन्हें ही उम्मीदवार बनाया जाएगा।

पार्टी टिकट पाने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों ने क्षेत्र में सक्रियता बढ़ा दी है। गली-मोहल्लों में संपर्क, बैठकों और व्यक्तिगत मुलाकातों पर जोर दिया जा रहा है। कुछ प्रभागों में तो इच्छुक और पूर्व नगरसेवकों ने प्रचार भी शुरू कर दिया है और अपनी उम्मीदवारी लगभग तय मानकर काम में जुट गए हैं। इसके बावजूद अंतिम समय तक असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि टिकट किसे मिलेगा और किसे नहीं। सभी दलों ने अपने-अपने कार्यकर्ताओं और इच्छुक उम्मीदवारों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पार्टी के खिलाफ कोई भी कदम न उठाया जाए।

बगावत की आशंका को देखते हुए नेतृत्व ने सावधानी बरतते हुए अंतिम निर्णय 30 दिसंबर को ही सार्वजनिक करने की रणनीति अपनाई है। उसी दिन एबी फॉर्म भी दिए जाने की तैयारी बताई जा रही है।

महापौर पद के आरक्षण पर भी नजरें टिकीं

महानगरपालिका चुनाव की प्रक्रिया के साथ ही महापौर पद के आरक्षण को लेकर भी राजनीतिक हलकों में उत्सुकता बढ़ गई है। 26 दिसंबर तक महापौर पद के आरक्षण की सोडत नहीं हो सकी है। अब यह आरक्षण कब घोषित होगा, इस पर सभी दलों की निगाहें टिकी हैं। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 15 जनवरी को मतदान होगा और 16 जनवरी को मतगणना की जाएगी। ऐसे में आने वाले दो-तीन दिन नांदेड की राजनीति के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं।

नगरपालिकाओं में महिलाओं का दबदबा, 8 नगराध्यक्ष सहित 151 महिला प्रतिनिधि निर्वाचित

नांदेड : हाल ही में संपन्न नगरपालिका चुनावों में महिलाओं ने ऐतिहासिक बढ़त हासिल करते हुए जिले की स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। जिले की 12 नगरपरिषदों और 1 नगरपंचायत सहित कुल 13 संस्थाओं में हुए चुनाव में 13 में से 8 नगराध्यक्ष पदों पर महिलाओं की जीत हुई है।

केवल नगराध्यक्ष ही नहीं, बल्कि नगरसेवक पदों पर भी महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ दिया है। कुल 269 नगरसेवक पदों में से 143 पदों पर महिला उम्मीदवार निर्वाचित हुई हैं, जबकि पुरुषों की संख्या 126 रही। प्रतिशत के हिसाब से सभागृह में 53.16 प्रतिशत महिलाएं और 46.84 प्रतिशत पुरुष प्रतिनिधि होंगे।

देगलूर नगरपरिषद में सबसे अधिक महिला प्रतिनिधि चुनी गई हैं, जहां नगराध्यक्ष सहित 27 महिला नगरसेवक सभागृह में होंगी। महिलाओं की इस मजबूत भागीदारी से नगर विकास, नागरिक सुविधाओं और प्रशासन में नई दिशा व गति मिलने की उम्मीद नागरिकों द्वारा व्यक्त की जा रही है।

मराठवाड़ा जनहित पार्टी महापालिका चुनाव लड़ेगी, नगर परिषद चुनाव में दो अध्यक्षों समेत 33 पार्षद निर्वाचित

नांदेड (संवाददाता) : हाल ही में संपन्न हुए नगर परिषद चुनावों में उल्लेखनीय सफलता हासिल करने वाली मराठवाड़ा जनहित पार्टी ने अब नांदेड-वाघाला शहर महानगरपालिका चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ने का निर्णय लिया है। यह जानकारी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव तथा बिलोली नगर परिषद के अध्यक्ष संतोष कुलकर्णी ने देशोन्नती से बातचीत में दी।

नांदेड जिले की 12 नगर परिषदों और एक नगर पंचायत के चुनाव हाल ही में संपन्न हुए थे। इन चुनावों में राष्ट्रीय और राज्य स्तर के प्रमुख राजनीतिक दल आमने-सामने थे। इसके बावजूद तेलंगाना सीमा से सटी बिलोली और धर्माबाद नगर परिषदों में नवगठित मराठवाड़ा जनहित पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास कराया।

बिलोली और धर्माबाद नगर परिषद चुनावों में पार्टी के दो नगराध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, जबकि कुल 33 नगरसेवक जीतकर आए हैं। इस सफलता के बाद पार्टी नेतृत्व ने आगामी 15 जनवरी को होने वाले नांदेड-वाघाला महानगरपालिका चुनाव में 15 से 20 वार्डों में उम्मीदवार उतारने का संकल्प लिया है।

संतोष कुलकर्णी ने बताया कि महापालिका चुनाव में दलित और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में पार्टी के अधिक उम्मीदवार मैदान में होंगे। उनका कहना है कि मराठवाड़ा जनहित पार्टी स्थानीय मुद्दों और जनहित के सवालों को लेकर चुनावी मैदान में उतरेगी।

राजनीतिक जानकारों के अनुसार, महापालिका चुनाव में मराठवाड़ा जनहित पार्टी की एंट्री से कांग्रेस को नुकसान होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर, पार्टी के इस फैसले से नांदेड की महापालिका राजनीति में मुकाबला और अधिक रोचक होने के आसार हैं।

नांदेड (संवाददाता): लोहा तहसील के चिंचोली शिवार से बहने वाली गोदावरी नदी के पात्र में पिछले कई महीनों से दिन-रात अवैध रूप से रेत का उत्खनन जारी है।

गोदावरी से दिन-रात अवैध रेत खनन; लोहा तहसील की कार्रवाई पर सवाल

यह सब कुछ राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों की आंखों के सामने हो रहा है, फिर भी जानबूझकर अनदेखी की जा रही है। नदी से रेत चोरी कर ले जाने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, यह सवाल अब आम नागरिक और किसान खुले तौर पर उठा रहे हैं।

जानकारी के अनुसार बिहार राज्य से लाए गए मजदूरों के जरिए बेड़ों (तराफों) की मदद से लगातार रेत निकाली जा रही है। रेत माफिया बेखौफ होकर नदीपात्र से रेत निकालकर अलग-अलग स्थानों पर उसका भंडारण कर रहे हैं। इसके बाद हाइवा टिप्पर के जरिए चोरी के रास्तों से रेत की तस्करी की जा रही है। खास बात यह है कि कापसी राजस्व मंडल कार्यालय और तलाठी कार्यालय के पास से रेत से भरे वाहन गुजरने के बावजूद कोई अधिकारी इन्हें रोकने की जहमत नहीं उठाता।

सरकार ने देवापुर-आमदुरा उच्चस्तरीय बंधारे का निर्माण तीन तहसीलों के किसानों को सिंचाई सुविधा देने के उद्देश्य से करोड़ों रुपये खर्च कर किया था। इस बंधारे से मुदखेड, लोहा और नांदेड तहसील के 21 गांवों को लाभ मिलना है। लेकिन इसी बंधारे के पायथ्य क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन खुलेआम जारी है, जिससे बंधारे के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। किसान इसको लेकर गंभीर चिंता जता रहे हैं।

येळी, कौडगाव, कामळज और चिंचोली गांवों के शिवार में कभी-कभार पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त कार्रवाई होती है। कुछ मशीनें तोड़ी जाती हैं और स्फोटकों से उत्खनन करने वाले उपकरण जब्त किए जाते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में फिर से वही अवैध कारोबार शुरू हो जाता है। इससे यह कार्रवाई महज दिखावा लगने लगी है।

<अब सवाल यह है कि आखिर रेत माफियाओं को किसका संरक्षण प्राप्त है और प्रशासन कब तक "हाथ पर हाथ रखे, मुंह पर उंगली" रखकर तमाशा देखता रहेगा?

स्वाधिकारी नंदिग्राम टाईम्स (नांदेड़) के मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक शेख जहूर शेख अहेमद द्वारा सहारा डिजाइनिंग एंड ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस, वाजेगांव, ता. व जि. नांदेड़ में मुद्रित तथा दैनिक नंदिग्राम टाईम्स, मुल्लाह मार्केट, खवी बिल्डिंग, नगरेश्वर मंदिर, नांदेड़–431604 (महाराष्ट्र) के कार्यालय से प्रकाशित। RNI-MAHHIN/2016/69743 मोबाइल संपर्क: 9921100075 | Email: ntinfodesk@gmail.com (वाद-विवाद हेतु न्यायक्षेत्र: नांदेड़ न्याय कक्षा में।)